वी. सेजप्पा

बनाम

राज्य द्वारा आरक्षी निरीक्षक लोकायुक्त, चित्रदुर्ग

(आपराधिक अपील संख्या 747/2008)

12 अप्रेल, 2016

[दीपक मिश्रा और आर. भानुमति, जे.जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 7, 13(1)(डी), 13(2)- परिवादी से उसके पेंशन कागजात पर कार्यवाही करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एक आधिकारिक कार्य करने के संबंध में 5000/- रुपये की अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति का आरोप- विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर दोषमुक्त करना कि अभियोजन पक्ष मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा और अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई मंजूरी आदेश प्राप्त नहीं किया गया था- राज्य की अपील पर, दोषमुक्ति को अपास्त कर दिया गया- दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील- अभिनिर्धारित किया गयाः अभियोजन स्वीकृति आदेश पी.डब्लू. 8, अवर सचिव, सरकार, पी.डब्लू. डी. से प्राप्त किया गया था- पी.डब्लू. 8 की साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए वैध स्वीकृति थी- मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जो कुछ भी स्थापित किया गया था वह अपीलकर्ता से धन की बरामदगी थी और केवल धन की बरामदगी अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा के लिए पर्याप्त नहीं थी- पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य से पी.डब्लू. 1 द्वारा अपीलकर्ता को डीजल की खरीद के लिए राशि का भुगतान किए जाने की मांग प्रमाणित नहीं हुई जिससे पी.डब्लू. 1 द्वारा अवैध परितोषण के रूप में राशि के भुगतान के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है- उच्च न्यायालय ने न तो

बचाव पक्ष की अन्यत्र रहने के तर्क पर विचार किया और न ही यह माना कि विचारण न्यायालय का निर्णय गलत या विकृत था- विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का आदेश पारित करते समय किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई खामी नहीं थी और जिन आधारों पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित था, उन्हें अनुचित नहीं कहा जा सकता- जबकि, उच्च न्यायालय का दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं था।

धारा 20 के तहत उपधारणा- अभिनिर्धारित कियाः यह साबित करने का आरंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है कि अभियुक्त ने विधिक पारिश्रमिक के अलावा अन्य राशि स्वीकार की या प्राप्त की- ऐसा तभी होता है जब अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति से संबंधित आरंभिक सबूत के भार का अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, तब बचाव साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है और अधिनियम की धारा 20 के तहत एक उपधारणा उत्पन्न हो जाएगी।

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील: उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा- अभिनिर्धारित किया गया: यदि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का मूल्याकंन और निष्कर्ष किसी अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है और जिन आधारों पर विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निकाला है, वे न्यायोचित और स्वीकार्य हैं, यदि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव हो तो भी उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. स्वीकृति आदेश पी.डब्लू. 8, अवर सचिव, शासन, लोक निर्माण विभाग से प्राप्त किया गया था। पी.डब्लू. 8 की साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति से संबंधित पत्रावली सचिव, लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी और इसे लोक निर्माण मंत्री को भेजा गया था और संतुष्ट होने पर लोक निर्माण मंत्री ने

स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दिए जाने के बाद, पी.डब्लू. 8 ने प्रदर्श पी-31 स्वीकृति आदेश जारी किया और इस प्रकार पी.डब्लू. 8 केवल प्रदर्श पी-31 जारी करके सरकार के निर्णय को क्रियान्वित कर रहा था। पी.डब्लू. 8 की साक्ष्य पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अपीलकर्ता पर अभियोजन संचालन के लिए वैध स्वीकृति जारी की गई थी।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध गठित करने के लिए, 'मांग का प्रमाण' अनिवार्य है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 09.12.1997 को, अपीलकर्ता ने पेंशन के लिए पी.डब्लू. 1 के आवेदन को अग्रेषित करने और उसकी सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान जारी करने के आधिकारिक कार्य को पूरा करने के लिए पी.डब्लू. 1 से अवैध परितोष के रूप में 5,000/- रुपये की मांग की। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने अन्यत्र होने की दलील दी है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 09.12.1997 को, वह वास्तव में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 07.12.1997 से 10.12.1997 तक बैंगलोर में आधिकारिक दौरे पर था और सेमिनार में भाग लेने के बाद, 10.12.1997 को, चित्रदुर्ग पी.एच.ई., उप खण्ड को आवंटित वैन उसने पी.डब्लू. 7 के साथ प्राप्त की। पी.डब्लू. 4 प्रथम श्रेणी सहायक, पी.एच.ई., चित्रदुर्ग ने अपनी जिरह में कहा है कि उपस्थिति रजिस्टर (प्रदर्श पी-16) की सामग्री के अनुसार, अपीलकर्ता की उपस्थिति से संबंधित कॉलम 03.12.1997 से 11.12.1997 तक खाली था। पी.डब्लू. 4 ने स्वीकार किया था कि 17.12.1997 को ट्रैप से लगभग एक सप्ताह पहले, चित्रदुर्ग पी.एच.ई., उप खण्ड को एक नई वैन आवंटित की गई थी और अपीलकर्ता और पी.डब्लू. 7, कनिष्ठ अभियंता ने बैंगलोर में वैन की डिलीवरी ली और उसे चित्रदुर्ग लेकर आये। बताया गया कि चित्रदुर्ग बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है, हालाँकि पी.डब्लू. 4 ने अपीलकर्ता के आधिकारिक दौरे के बारे में विशेष रूप से बात नहीं की है, लेकिन तथ्य यह है कि 10.12.1997 को, अपीलकर्ता ने चित्रदुर्ग पी.एच.ई.,

उप खण्ड को आवंटित वैन को बेंगलुरु से प्राप्त किया। पी.डब्लू. 5, जो बैंगलौर में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधिशाषी अभियंता के रूप में कार्यरत था, ने अपनी जिरह में कहा कि अपीलकर्ता बैंगलोर में 09.12.1997 की एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 08.12.1997 को आया था। इसके अलावा, पी.डब्लू. 7, जो चित्रदुर्ग में वेल बोरिंग उप खण्ड में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत था, ने अपनी जिरह में बताया कि वह अपीलकर्ता के साथ 09.12.1997 को बैंगलोर में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए गया था। उपस्थिति रजिस्टर प्रदर्श पी-16 के साथ पी.डब्ल्यू. 4, 5 और 7 की साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्रतिरक्षा में बताया गया कि अपीलकर्ता 08.12.1997 से 10.12.1997 तक चित्रदुर्ग स्थित कार्यालय में मौजूद नहीं था और अत्यधिक संभावित है कि वह 09.12.1997 को बैंगलोर में सेमिनार में भाग ले रहा था। साक्ष्य का मूल्यांकंन करते हुए विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि 09.12.1997 को अपीलकर्ता ने पी.डब्लू. 1 से 5,000/- रुपये की मांग की थी। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष एक उचित संभावित दृष्टिकोण था जिसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। [पैरा 10 से 14]

3. पी.डब्लू. 1 स्पेशल ग्रेड कनिष्ठ अभियंता चित्रदुर्ग के पद से 31.10.1997 को सेवानिवृत्त हुआ। पी.डब्लू. 1 का सेवा रजिस्टर 22.11.1997 को बोरवेल उप खण्ड, चित्रदुर्ग को भेजा गया था। पी.डब्लू. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दी है कि उसने अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और चूंकि पी.डब्लू. 1 ने इसके लिए कोई कवरिंग पत्र नहीं दिया था इस कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, 04.12.1997 को, पी.डब्लू. 1 ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु कवरिंग लेटर दिया गया। पी.डब्लू. 4 ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है अपीलकर्ता के निर्देशानुसार प्रदर्श डी-2 (04.12.1997) के अनुसार, 07.12.1997 को पी.डब्लू. 4 ने एक विस्तृत नोट तैयार किया। पी.डब्लू. 4 ने आगे यह अभिकथन किया है कि दिनांक 07.10.1997 से

10.10.1997 तक अपीलकर्ता की कार्यालय में अनुपस्थिति के कारण वह अपीलकर्ता के समक्ष कार्यालय नोट (प्रदर्श डी-2) नहीं रख सका और पी.डब्लू. 4 ने 11.12.1997 को प्रदर्श डी-2 अपीलकर्ता के समक्ष रखा। यह भी पी.डब्लू. 1 की साक्ष्य है कि अपनी पेंशन की कार्यवाही के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ सत्यापित नहीं थे जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। पी.डब्लू. 1 को पता था कि उससे उचित सत्यापन के बाद इन दस्तावेजों को जमा करने की उम्मीद की गई थी। पी.डब्लू. 4 की साक्ष्य और दस्तावेजों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान के लिए कागजात सामान्य तरीके से संसाधित किए गए थे। [पैरा 15]

4. धनराशि स्वीकार करने के संबंध में पी.डब्लू. 1 और 2 की साक्ष्य के अनुसार, 17.12.1997 को, पी.डब्लू. 1, पी.डब्लू. 2 के साथ अपीलकर्ता के कार्यालय में गया, छापा मारने वाली पार्टी और पी.डब्लू. 3 कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे। पी.डब्लू. 2 अपीलकर्ता के कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था और कमरे के अंदर, पी.डब्लू. 1 ने अपीलकर्ता को अभिकथित मुद्रा सौंपी। पी.डब्लू. 1 से संकेत मिलने पर, छापा मारने वाली पार्टी और पी.डब्लू. 3 ने अपीलकर्ता के कार्यालय में प्रवेश कर और अभिकथित नोटों को अपीलार्थी से बरामद किया। पी.डब्लू. 2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है कि वह अपीलकर्ता के कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था और उसने पी.डब्लू. 1 को अपीलकर्ता को यह कथन करते हुए 5,000/- रुपये की राशि देते हुए देखा कि *'उसने अभियुक्त से डीजल क्रय करने के लिए जो राशि ली उसको वापस कर रहा है'*। पी.डब्लू. 2 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि वह अपीलकर्ता को अवैध परितोषण के रूप में धन का भुगतान करने के संबंध में वह अभियोजन मामले का समर्थन करने में विफल रहा। इस प्रकार पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य अवैध परितोषण की स्वीकृति और अभियोजन मामले के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। [पैरा 16, 17]

5. यह सुस्थापित है कि अभियुक्त ने कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य राशि स्वीकार की या प्राप्त की यह साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है। ऐसा तभी होता है जब अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति के संबंध में इस प्रारंभिक भार का अभियोजन पक्ष द्वारा सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाता है, तब बचाव साबित करने का भार आरोपी पर अंतरित हो जाता है और अधिनियम की धारा 20 के तहत एक उपधारणा उत्पन्न होती है। उक्त मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जो कुछ भी स्थापित किया गया है वह अपीलकर्ता से धन की बरामदगी थी और केवल धन की बरामदगी अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा के लिए पर्याप्त नहीं थी। केवल इसलिए कि साक्ष्य के पुनर्विवेचन अैार पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है तो दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं है। 09.12.1997 को मांग के सबूत की अनुपस्थिति, पी.डब्लू. 1 द्वारा अपीलकर्ता को डीजल की खरीद के लिए राशि का भुगतान किया जाना जो पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य से समर्थित है जिससे पी.डब्लू. 1 द्वारा अवैध परितोषण के रूप में भुगतान की गई राशि के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। उच्च न्यायालय ने न तो अन्य जगह उपस्थित (Plea of alibi) के बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा पर विचार किया और न ही यह माना कि विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण या विकृत था। दोषमुक्ति का आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन किसी भी कमजोरी या अवैधता या अभिव्यक्त त्रुटि से ग्रस्त नहीं है और जिन आधारों पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है, उन्हें अनुचित नहीं कहा जा सकता है। दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। [पैरा 18, 21, 24, 25]

बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एससीसी 55: 2014 (4) एससीआर 554; पी सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक. आंध्र प्रदेश राज्य

और अन्य (2015) 10 एससीसी 152; सुरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 4 एससीसी 725; सी.एम गिरीश बाबू बनाम सी.बी.आई. कोचीन केरला उच्च न्यायालय, (2009) 3 एससीसी 779: 2009 (2) एससीआर 1021; केरल राज्य और अन्य बनाम सी.पी. राव (2011) 6 एससीसी 450: 2011 (6) एससीआर 864; मुकुट बिहारी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2012) 11 एससीसी 642: 2012 (6) एससीआर 710; राज्य जरिए पुलिस निरीक्षक आन्ध्र प्रदेश बनाम के नरसिम्हाचमी (2005) 8 एससीसी 364: 2005 (4) पूरक एससीआर 197; टी सुब्रमण्यन बनाम तिमलनाडू राज्य (2006) 1 एससीसी 401: 2006 (1) एससीआर 180; मुरलीधर उर्फ गिद्दा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2014) 5 एससीसी 730: 2014 (4) एससीआर 817- पर विश्वास किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 747/2008

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आपराधिक अपील संख्या 851/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.2008 से।

तारा चंद्र शर्मा, सुश्री रजनी के. प्रसाद, सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, टी.वी. रत्नम- अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।

वी. एन. रघुपति- एडवोकेट, प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय **आर. भानुमति, जे** द्वारा सुनाया गयाः

1. यह अपील आपराधिक अपील संख्या 851/2002 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2008 को चुनौती देती है, जिससे राज्य द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

2. परिवादी एन.रामकृष्णप्पा (पी.डब्लू. 1) चित्रदुर्ग में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वेल बोरिंग उप खण्ड में स्पेशल ग्रेड कनिष्ठ अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ। शिकायतकर्ता को डी.सी.आर.जी. व अवकाश के नकदीकरण सुविधा के अलावा अन्य सेवा लाभ जैसे समूह बीमा राशि, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति, जी.पी.एफ. 10.11.1997 व 14.11.1997 को प्राप्त हुए। आरोपी तब चित्रदुर्ग में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के उसी वेल बोरिंग उप खण्ड का सहायक अधिशाषी अभियंता था। 16.12.1997 को, पी.डब्लू. 1 शिकायतकर्ता ने पुलिस निरीक्षक लोकायुक्त, चित्रदुर्ग के समक्ष एक मौखिक शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 09.12.1997 को, आरोपी ने उसके पेंशन कागजात और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को प्रक्रियाधीन करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन. अे ा.सी.) सौंपने हेतु उससे अवैध परितोषण के रूप में 5,000/- रुपये की मांग की।उक्त शिकायत के आधार पर, पी.डब्लू. 12 लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक ने अपराध संख्या 6/97 में अपीलकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की। पी.डब्लू. 12 ने दिनांक 17.12.1997 को अभियुक्त का े पकडने की व्यवस्था की। 17.12.1997 को प्रातः लगभग 10.15-10.25 बजे, छापा मारने वाला दल ओबैया (पी.डब्लू. 2) और आर.वी. श्रीनिवासा (पी.डब्लू. 3) परिवादी एन.रामकृष्णप्पा (पी.डब्लू. 1) के साथ आरोपी के कार्यालय में गया। छापेमारी दल और पी.डब्लू. 3 कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे। पी.डब्लू. 1 और पी.डब्लू. 2 कार्यालय में गए और यह अभिकथित है कि आरोपी ने पी.डब्लू. 1 से 5,000/- रुपये की मांग की, पी.डब्लू. 1 ने 5,000/- रुपये के नोट दिए और आरोपी ने पैसे प्राप्त किए और एक डायरी में रख लिए और डायरी उसकी मेज के अंदर रखी हुई थी।

पी.डब्लू. 1 से संकेत मिलने पर छापेमारी दल ने आरोपी के कार्यालय में जाकर आरोपी से पूछताछ की और आरोपी के पास से 5,000/- रुपये की राशि बरामद की। जब आरोपी का दाहिना हाथ सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोया गया तो वह भी पॉजिटिव पाया गया।सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने और जांच पूरी होने पर, उपर्युक्त अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया था।

3. अभियुक्त के विरूद्ध अपराध स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने बारह गवाहों को परीक्षित कराया और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-34 तक के दस्तावेज प्रदर्श चिन्हित कराए और भौतिक वस्तुओं को एम ओएस. 1 से 18 तक प्रदर्श अंकित कराया गया। अपीलकर्ता-अभियुक्त से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दोषसिद्धकारी साक्ष्य और परिस्थितियों के संबंध में परीक्षित किया गया। आरोपी ने मांग से इनकार किया और अभिकथन किया कि 09.12.1997 को, वह आधिकारिक कर्त्तव्य पर बैंगलोर में था उसके खिलाफ एक झूठा मामला संस्थित किया गया था। आरोपी ने प्रदर्श डी-1 से डी-8 तक के दस्तावेज पेश किए हैं। साक्ष्य पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने यह तय किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा पी.डब्लू. 1 से उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों के समाधान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए रूपए 5000/- के अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय ने यह भी तय किया कि पी.डब्लू. 8 एस.सम्पथ, अवर सचिव, सरकार, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी-31 में अभियुक्त को अभियोजित करने की स्वीकृति देने के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा संदर्भित दस्तावेजों का कोई उल्लेख नहीं होने से यह माना कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई वैध स्वीकृति नहीं थी और इस तरह आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

4. दोषमुक्ति के आदेश से व्यथित होकर राज्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। उच्च न्यायालय ने विचारण

न्यायालय के निष्कर्ष को पलट दिया और माना कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन संचालित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा वैध स्वीकृति आदेश प्राप्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू.1 का एक आधिकारिक कार्य करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा 5,000/- रुपये की अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को साबित कर दिया है और आरोपी को अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत छह महीने के कारावास की सजा सुनाई और उसे अधिनियम की धारा 13(2) सपठित धारा 13(1) (डी) के तहत दो साल के कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया। व्यथित होकर अपीलकर्ता-अभियुक्त ने यह अपील दायर की है।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री तारा चंद शर्मा ने तर्क दिया कि 09.12.1997 को रिश्वत की कोई मांग नहीं की जा सकती थी और उच्च न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क को मानने में विफल रहा कि अपीलकर्ता 07.12.1997 से 10.12.1997 तक बैंगलोर में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए अपनी आधिकारिक कर्तव्य पर होने से चित्रदुर्ग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ था और 10.12.1997 की सायं को, अपीलकर्ता ने पी.डब्लू. 7 के साथ बैंगलोर में चित्रदुर्ग पीएचई, उप-खण्ड को आवंटित एक वैन प्राप्त की थी। आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य को नजरअंदाज करके गलती की है, जिसने विशेष रूप से कहा है कि अपीलकर्ता को 5,000/- रुपये की राशि दी थी, जिसमें कहा गया था कि पी.डब्लू. 1 ने डीजल खरीदने हेतु लिए गए पैसा वापस किए। आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आलोक में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा का उचित मूल्याकंन करने में विफल रहा और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एन. रघुपति ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य का मूल्याकंन करने पर, उच्च न्यायालय ने सही माना था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा एक आधिकारिक कार्य 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जारी करने के संबंध में 5,000/- रुपये की अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को स्थापित करके अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।

7. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय, विचारण न्यायालय के निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया।

8. इससे पहले कि हम अभियोजन पक्ष की अेार से अपीलकर्ता द्वारा अवैध परितोषण की प्रस्तुत मांग एवं स्वीकृति के प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करें, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श पी-31 स्वीकृति आदेश के संबंध में जो निष्कर्ष दिया है उसको संदर्भित कर सकते हैं। स्वीकृति आदेश पी.डब्लू. 8, अवर सचिव, शासन, लोक निर्माण विभाग से प्राप्त किया गया था। विचारण न्यायालय ने यह दृष्टिकोंण अपनाया कि अभियोजन संचालित करने के लिए कोई वैध स्वीकृति नहीं थी क्योंकि स्वीकृति आदेश में उस प्राधिकारी का कोई संदर्भ नहीं था जिसने अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का निर्णय लिया था और अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय अपीलकर्ता के विरूद्ध *प्रथम दृष्टया* मामले के बारे में संतुष्ट होने के लिए प्राधिकारी द्वारा संदर्भित दस्तावेजों का भी कोई संदर्भ नहीं था। विचारण न्यायालय ने यह दृष्टिगत किया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा जो यह सुझाव दे सके कि अधिनियम की धारा 19 के आधार पर सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्तियां पी.डब्लू. 8 को सौंपी गई थीं और इसलिए यह माना गया कि अपीलकर्ता को अभियोजित करने के लिए अभियोजन ने वैध मंजूरी आदेश प्राप्त नहीं किया।

9. इसके विपरीत, पी.डब्लू. 8 संपत की साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता को अभियोजित करने के लिए वैध स्वीकृति थी और पी.डब्लू. 8, अवर सचिव केवल प्रदर्श पी-31 स्वीकृति आदेश जारी करके सरकार के निर्णय को क्रियान्वित कर रहा था। पी.डब्लू. 8 की साक्ष्य के अनुसार, अपीलकर्ता पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति से संबंधित पत्रावली सचिव, लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी और इसे लोक निर्माण मंत्री को भेजा गया था और संतुष्ट होने पर लोक निर्माण मंत्री ने स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दिए जाने के बाद, पी.डब्लू. 8 ने प्रदर्श पी-31 स्वीकृति आदेश जारी किया और इस प्रकार पी.डब्लू. 8 केवल प्रदर्श पी-31 जारी करके सरकार के निर्णय को क्रियान्वित कर रहा था। पी.डब्लू. 8 की साक्ष्य पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि अपीलकर्ता पर अभियोजन संचालन के लिए वैध स्वीकृति जारी की गई थी। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। विस्तृत जानकारी के अनुसार, चूंकि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता द्वारा 'अवैध संतुष्टि' की मांग और स्वीकृति को स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए हम 'स्वीकृति के पहलू पर और अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

10. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अपराध गठित करने हेतु 'मांग का प्रमाण' अनिवार्य है। इस न्यायालय के हाल के निर्णय बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2014) 13 एससीसी 55 सहित कई निर्णयों में इसकी पुष्टि की गई है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

> "7. जहां तक धारा 7 के तहत अपराध का प्रश्न है, यह स्थापित विधिक स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध के गठन के लिए अपरिहार्य है और केवल मुद्रा नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध गठित नहीं करता जब तक कि सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह साबित न हुआ हो कि आरोपी ने यह जानते हुए कि यह

रिश्वत है, स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए। इस न्यायालय के कई निर्णयों में उपरोक्त स्थिति को सारगर्भित रूप से बताया गया है। उदाहरण के तौर पर सी.एम. शर्मा बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई (2009) 3 एससीसी 779 के मामले के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।"

पी.सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 10 एस.सी.सी. के मामले में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था।

11. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 09.12.1997 को अपीलार्थी ने पी.डब्लू. 1 से उसकी पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ जारी करने के लिए पी.डब्लू. 1 के आवेदन को अग्रेषित करने के कार्यालयी कार्य के निर्वहन करने के लिए अवैध परितोष के रूप में 5,000/- रुपये की मांग की। पी.डब्लू. 1-रामकृष्णप्पा ने बताया है कि 09.12.1997 को, अपीलकर्ता ने उसके पेंशन कागजात को प्रक्रियाधीन करने हेतु महालेखाकार कार्यालय, बैंगलोर में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भेजने के लिए अवैध परितोषण के रूप में 5,000/- रुपये की मांग की थी। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने अन्यत्र होने की दलील दी है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 09.12.1997 को, जब उस पर चित्रदुर्ग स्थित अपने कार्यालय में अवैध परितोषण की मांग करने का आरोप अभिकथित किया गया, तब वह वास्तव में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए 07.12.1997 से 10.12.1997 तक बैंगलोर में आधिकारिक दौरे पर था और सेमिनार में भाग लेने के बाद, 10.12.1997 को, उसने पी.डब्लू. 7 के साथ चित्रदुर्ग पीएचई, उप खण्ड को आवंटित की गई वैन की डिलीवरी ली।

12. परस्पर विपरीत तर्कों के विवेचन करने के लिए, पी.डब्लू. 4 और 5 के साक्ष्य प्रासंगिक हो जाती है। पी.डब्लू. 4 मो. शफीउल्ला, प्रथम श्रेणी सहायक, वेल

बोरिंग उप खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्रदुर्ग ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उपस्थिति रजिस्टर (प्रदर्श पी-16) की सामग्री के अनुसार, अपीलकर्ता की उपस्थिति से संबंधित कॉलम 03.12.1997 से 11.12.1997 तक रिक्त था। पी.डब्लू. 4 ने स्वीकार किया था कि 17.12.1997 को ट्रैप से लगभग एक सप्ताह पहले, चित्रदुर्ग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, उप खण्ड को एक नई वैन आवंटित की गई थी और अपीलकर्ता और पी.डब्लू. 7 पम्पन्ना, कनिष्ठ अभियंता ने बैंगलोर में वैन की डिलीवरी ली थी और इसे चित्रदुर्ग ले आए। बताया गया कि चित्रदुर्ग बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यद्यपि पी.डब्लू. 4 ने अपीलकर्ता के आधिकारिक यात्रा के बारे में विशेष रूप से नहीं बताया है, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने 10.12.1997 को चित्रदुर्ग पीएचई, उप खण्ड को आवंटित वैन की डिलीवरी बैंगलोर से ली थी।

13. पी.डब्लू. 5 ए.एम.प्रभाकर, जो 01.06.1996 से 18.12.1999 तक वेल बोरिंग खण्ड, पीएचई, बैंगलोर में अधिशाषी अभियंता के रूप में कार्यरत था, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि अपीलकर्ता 09.12.1997 की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 08.12.1997 को बैंगलोर आया था। पी.डब्लू. 5 ने आगे कहा है कि 10.12.1997 को पीएचई, उप खण्ड, चित्रदुर्ग को आवंटित वैन की डिलीवरी लेने के बाद, अपीलकर्ता सायंकाल में बैंगलोर से चला गया। वेल बोरिंग खण्ड, पीएचई, बैंगलोर में अधिशाषी अभियंता के रूप में कार्यरत पी.डब्लू. 5 ए.एम.प्रभाकर की साक्ष्य पर बहुत अधिक विश्वास किया जाना चाहिए क्योंकि वह 09.12.1997 को बैंगलोर में एक सेमिनार में अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में बोलने के लिए सक्षम साक्षी हैं। इसके अलावा, पी.डब्लू. 7 पम्पन्ना, जो कि वेल बोरिंग उप खण्ड, चित्रदुर्ग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत था, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है कि वह अपीलकर्ता के साथ 09.12.1997 को बैंगलोर में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए गया था। पी.डब्लू. 7 ने

आगे कहा कि 10.12.1997 को अपीलकर्ता और उसने पीएचई वेल बोरिंग उप खण्ड, चित्रदुर्ग को आवंटित वैन की डिलीवरी ली और उक्त वैन में यात्रा की और वे लगभग 3.00 बजे बेंगलुरु से रवाना हुए और 10.12.1997 को शाम 7.30 बजे चित्रदुर्ग पहुंचे।

14. उपस्थिति रजिस्टर प्रदर्श पी-16 के साथ पी.डब्लू. 4, 5 और 7 की साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्रतिरक्षा में बताया गया है कि अपीलकर्ता 08.12.1997 से 10.12.1997 तक चित्रदुर्ग स्थित कार्यालय में मौजूद नहीं था और अत्यधिक संभावित है कि वह 09.12.1997 को बैंगलोर में सेमिनार में भाग ले रहा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, पी.डब्लू. 1 ने इस सुझाव से इंकार किया है कि 09.12.1997 को अपीलकर्ता अपने कार्यालय में काम नहीं कर रहा था और वह अपीलकर्ता से नहीं मिला था। हालाँकि, अपीलकर्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि प्रदर्श पी-19 के रूप में चिह्नित एक डायरी में, अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि 08.12.1997 को वह बैंगलोर में खण्ड कार्यालय में बैठक में शामिल हुआ था और उसने 10.12.1997 को एक वैन की डिलीवरी ली थी। साक्ष्य का मूल्याकंन करते हुए विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि 09.12.1997 को अपीलकर्ता ने पी.डब्लू. 1 से 5,000/- रुपये की मांग की थी। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य आधारित एक उचित संभावित दृष्टिकोण था हमारी राय में, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

15. अब पी.डब्लू. 1 के दावा, जिस उद्देश्य के लिए उसने रिश्वत की राशि का भुगतान किया था, उस पर विचार करने पर जैसा कि पूर्व में अवलोकन किया गया है, पी.डब्लू. 1 स्पेशल ग्रेड कनिष्ठ अभियंता, चित्रदुर्ग के पद से 31.10.1997 को सेवानिवृत्त हुआ। पी.डब्लू. 1 का सेवा रजिस्टर 22.11.1997 को बोरवेल उप खण्ड, चित्रदुर्ग को भेजा गया था। पी.डब्लू. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दी है कि उसने अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और चूंकि पी.डब्लू. 1 ने इसके लिए कोई कवरिंग पत्र

नहीं दिया था इस कारण इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, 04.12.1997 को, पी.डब्लू. 1 ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु कवरिंग लेटर दिया। पी.डब्लू. 4 मोहम्मद शफीउल्ला ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता के निर्देशानुसार व प्रदर्श डी-2 (04.12.1997) के अनुसार, 07.12.1997 को पी.डब्लू. 4 ने एक विस्तृत नोट तैयार किया। पी.डब्लू. 4 ने आगे यह अभिकथन किया है कि दिनांक 07.10.1997 से 10.10.1997 तक अपीलकर्ता की कार्यालय में अनुपस्थिति के कारण वह अपीलकर्ता के समक्ष कार्यालय नोट (प्रदर्श डी-2) नहीं रख सका और पी.डब्लू. 4 ने 11.12.1997 को प्रदर्श डी-2 अपीलकर्ता के समक्ष रखा। पी.डब्लू. 1 की यह भी साक्ष्य है कि अपनी पेंशन की कार्यवाही के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ (प्रदर्श पी-6 से पी-15) सत्यापित नहीं थे जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। पी.डब्लू. 1 को पता था कि उससे उचित सत्यापन के बाद इन दस्तावेजों को जमा करने की उम्मीद की गई थी। प्रदर्श पी-6 से पी-15 को निर्दिष्ट करते हुए विचारण न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है-

> "...प्रदर्श पी-3 से पी-15 के रूप में चिह्नित दस्तावेज़ों की सामग्री से, यह संभाव्य प्रकट नहीं है कि पी.डब्लू. 1 ने 02.12.97 को पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं। वहीं दूसरी ओर इन दस्तावेज़ों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ये दस्तावेज़ 17.12.97 को अस्तित्व में लाए गए..."

पी.डब्लू. 4 की साक्ष्य और दस्तावेजों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति लाभों के निपटान के लिए कागजात पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही की गई।

16. उपरोक्त पृष्ठभूमि में मांग के सबूत के अभाव के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष का मामला और पी.डब्लू. 1 और 2 की साक्ष्य को पैसे की स्वीकृति के संबंध में सूक्ष्मता से विवेचन की मांग करता है। 17.12.1997 को, पी.डब्लू. 1 रामकृष्णप्पा, पी.डब्लू. 2 ओबैया के साथ अपीलकर्ता के कार्यालय गए और छापेमारी दल व पी.डब्लू. 3 श्रीनिवास कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे। पी.डब्लू. 2 ओबैया अपीलकर्ता के कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था और कमरे के अंदर पी.डब्लू. 1 ने अपीलकर्ता को अभिकथित मुद्रा सौंपी थी। पी.डब्लू. 1 से संकेत मिलने पर, छापा मारने वाले दल और पी.डब्लू. 3 ने अपीलकर्ता के कार्यालय में प्रवेश किया और अपीलकर्ता के कब्जे से अभिकथित मुद्रा नोट बरामद किए गए।

17. पी.डब्लू. 2 ने अपनी अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वह अपीलकर्ता के कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था और उसने पी.डब्लू. 1 को अपीलकर्ता को यह कथन करते हुए 5,000/- रुपये की राशि देते हुए देखा कि *'वह डीजल खरीदने के लिए आरोपी से ली गई राशि वापस कर रहा है'।* पी.डब्लू. 2 ने आगे कथन किया है कि पी.डब्लू. 3 और लोकायुक्त पुलिस ने अपीलकर्ता के कार्यालय में प्रवेश किया और अपीलकर्ता के पास से मुद्रा नोट बरामद किए गए और जब अपीलकर्ता का दाहिना हाथ सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोया गया तो वह गुलाबी हो गया। अपनी जिरह में, पी.डब्लू. 2 ओबैया ने इस सुझाब से इंकार किया कि अपीलकर्ता ने पेंशन कागजात को अग्रेषित करने के लिए रिश्वत के रूप में पी.डब्लू. 1 से 5,000/- रुपये की राशि की मांग की और रूपए देने पर उनको स्वीकार किया। पी.डब्लू. 2 ने अभियोजन के इस मामले का समर्थन नहीं किया कि पी.डब्लू. 1 ने अपीलकर्ता को रिश्वत के रूप में 5,000/- रुपये दिए थे; बल्कि, पी.डब्लू. 2 ने कहा कि अपीलकर्ता को राशि देते समय, पी.डब्लू. 1 ने कहा कि यह खरीदे गए डीजल की राशि के बदले में है। पी.डब्लू. 2 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने अपीलकर्ता को अवैध परितोषण के रूप में

धन का भुगतान करने के संबंध में अभियोजन मामले का समर्थन करने में विफल रहा। इस प्रकार पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य अवैध परितोषण की स्वीकृति और अभियोजन मामले के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।

18. यह सुस्थापित है कि अभियुक्त ने विधिक पारिश्रमिक के अलावा अन्य राशि स्वीकार की या प्राप्त की यह साबित करने का आरंभिक भार अभियोजन पक्ष पर है। जब अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति के संबंध में आरंभिक भार को अभियोजन पक्ष द्वारा उन्मोचित कर दिया जाता है, तब प्रतिरक्षा का भार आरोपी पर अंतरित हो जाता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा की जा सकती है। मौजूदा मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जो कुछ भी स्थापित किया गया है वह अपीलकर्ता से धन की बरामदगी होना ही है औार केवल धन की बरामदगी अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा के लिए पर्याप्त नहीं थी।

19. सी.एम. गिरीश बाबु बनाम सी.बी.ई. कोचीन, केरल उच्च न्यायालय (2009) 3 एससीसी 779 के मामले में सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 4 एससीसी 725 काे निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि-

> "18. सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह विचार किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, पैरा 2 पर) केवल धन की बरामगदी उन परिस्थितियों से पृथक है जिनमें यह भुगतान किया गया, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है जबकि मामले में सारभूत साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं हैं। रिश्वत के भुगतान को साबित करने के लिए या यह दिखाने के लिए कि आरोपी ने स्वेच्छा से यह जानते हुए कि यह रिश्वत है, धन स्वीकार

किए हैं, किसी सबूत के अभाव में केवल बरामदगी ही आरोपी के खिलाफ अभियोजन के आरोप को साबित नहीं कर सकती है।"

केरल राज्य और अन्य बनाम बनाम सी.पी. राव (2011) 6 एससीसी 450, के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल धन की बरामदगी ही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है इसके लिए रिश्वत की मांग के संबंध में परिवादी की साक्ष्य से पुष्टि होनी चाहिए।

20. जहां तक इस तर्क का प्रश्न है कि यह पर्याप्त नहीं है कि कुछ मुद्रा नोट लोक सेवक को अवैध परितोषण बनाने के लिए सौंपे गए थे और अभियोजन पक्ष का यह साबित करने का अतिरिक्त कर्तव्य है कि जो भुगतान किया गया था वह एक अवैध परितोषण था, इस संदर्भ में मुकुट बिहारी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2012) 11 एससीसी 642 को संदर्भित किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किया गया-

"11. इस मुद्दे पर विधि सुस्थापित है कि अधिनियम, 1988 के तहत अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग अनिवार्य है। केवल भ्रष्ट/दूषित धन की बरामदगी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि रिश्वत का भुगतान साबित करने या यह दिखाने के लिए कि पैसा रिश्वत के रूप में स्वेच्छा से लिया गया, के संबंध में सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। धनराशि की मांग अैर स्वीकृति के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, आरोपी द्वारा अवैध परितोष के रूप में केवल धनराशि की प्राप्ति अपराध से आबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत वैधानिक उपधारणा को उचित प्रायकिता के साथ प्रत्यक्ष या

परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अभिलेख पर लाकर यह स्थापित करने के लिए कि पैसा उसके द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 7 में उल्लिखित उददेश्य या इनाम के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार किया गया था को, खण्डित करने का भार अभियुक्त पर होता है। अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को लागू करते समय, न्यायालय को आरोपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर केवल संभाव्यता की प्रधानता की कसौटी पर, न कि सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाण की कसौटी पर विचार करना आवश्यक है। हालाँकि, इससे पहले कि अभियुक्त को यह स्पष्टीकृत करने लिए कहा जाए कि उसके पास प्रश्नगत राशि कैसे पाई गई, अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्य स्थापित किया जाना आवश्यक है। परिवादी ट्रैप की सफलता से संबद्ध एक हितबद्ध और पक्षपातपूर्ण गवाह है उसके साक्ष्य का परीक्षण उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य इच्छुक गवाह का और उचित मामले में न्यायालय आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने से पहले स्वतंत्र पुष्टि की तलाश कर सकती है।"

21. यदि साक्ष्य एवं विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष के मूल्यांकन से जिन आधारों पर विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निकाला है, वे युक्तियुक्त और विश्वसनीय है और किसी अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं है, तब यदि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव हो तो भी उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश को नहीं उलटना चाहिए। केवल इसलिए कि साक्ष्य के पुर्नविवेचन और पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का इच्छुक है एवं यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है तो दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप उचित नहीं है। राज्य जरिए पुलिस निरीक्षक, आन्ध्र प्रदेश बनाम के. नरसिम्हाचारी (2005) 8

एससीसी 364 के माध्यम से, इस न्यायालय ने इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और केवल जहां अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अभियुक्त के दोषी होने के अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है, दोषमुक्त करने के फैसले में अपीलीय न्यायाल के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडू राज्य (2006) 1 एससीसी 401 के मामले में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था।

22. मुरलीधर उर्फ गिद्दा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2014) 5 एससीसी 730, के मामले में इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जिनका दोषमुक्ति के आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है और पैराग्राफ (12) में यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "12. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण पर इस न्यायालय द्वारा तुलसीराम कानू एआईआर 1954 एससी 1, मदन मोहन सिंह एआईआर 1954 एससी 637, एटली एआईआर 1955 एससी 807, अहेर राजा खीमा एआईआर 1956 एससी 217, बलबीर सिंह एआईआर 1957 एससी 216, एमजी अग्रवाल एआईआर 1963 एससी 200, नूर खान एआईआर 1964 एससी 286, खेदू मोहटन (1970) 2 एससीसी 450, शिवाजी साहबराव बोबडे (1973) 2 एससीसी 793, लेखा यादव (1973) 2 एससीसी 424, खेम करण (1974) 4 एससीसी 603, बिशन सिंह (1974) 3 एससीसी 288, उम्मेदभाई जादवभाई (1978) 1 एससीसी 228, के. गोपाल रेड्डी (1979) 1 एससीसी 355, तोता सिंह (1987) 2 एससीसी 529, राम कुमार (1995) सप्लीमेंट्री 1 एससीसी 248, मदन लाल (1997) 7

एससीसी 677, संबासिवन (1998) 5 एससीसी 412, भगवान सिंह (2002) 4 एससीसी 85, हरिजन थिरुपला (2002) 6 एससीसी 470, सी. एन्टनी (2003) 1 एससीसी 1, के. गोपालकृष्ण (2005) 9 एससीसी 291, संजय ठकरान (2007) 3 एससीसी 755 और चंद्रप्पा (2007) 4 एससीसी 415 में विचार किया गया है। इनमें से प्रत्येक मामले को विचारगत किया जाना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है कि इस न्यायालय ने लगातार माना है कि दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील के निस्तारण में, अपीलीय अदालत को निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए:-

(i) किसी आरोपी व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा है और ऐसी उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश से मजबूत होती है;

(ii) जब दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील की योग्यता को दृष्टिगत किया जावे तो अभियुक्त व्यक्ति उचित संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है;

(iii) हालाँकि, दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील पर विचार करने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील में उसकी शक्तियों के जितनी ही व्यापक हैं, लेकिन अपीलीय न्यायालय आम तौर पर विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से बचती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचारण न्यायालय को गवाहों के आचरण को देखने का लाभ था। यदि विचारण न्यायालय मामले के तथ्यों पर युक्तियुक्त दृष्टिकोंण अपनाता है, तो दोषमुक्ति के निर्णय में

अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जब तक कि, विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत नहीं हैं या कानून के गलत दृष्टिकोंण पर आधारित हैं या यदि ऐसे निष्कर्ष को कायम रहने दिया जाता है, तो उनके परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय होने की संभावना है, ऐसे निष्कर्षों में अपीलीय न्यायालय की ओर से हस्तक्षेप करने में अनिच्छा पूरी तरह से न्यायोचित है; और

(iv) केवल इसलिए कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के की पुनर्विवेचन और पुनर्मूल्यांकन पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं है। साक्ष्य के समान रूप से संतुलित विचारों के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय के फैसले में अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

23. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और परिस्थितियों: (i) शिकायत दर्ज करने में देरी; (ii) यद्यपि अपीलकर्ता पर 09.12.1997 को चित्रदुर्ग में मांग करने का आरोप है, किन्तु 07.12.1997 से 10.12.1997 तक चित्रदुर्ग में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति और मांग की साक्ष्य की अनुपस्थिति; (iii) पी.डब्लू. 1 द्वारा पेंशन कागजात को प्रक्रियागत करने और सेवानिवृत्ति परिलाभों का निपटान करने के लिए दस्तावेजों प्रदर्श पी-6 से पी-15 तक को प्रस्तुत करने के संबंध में उठाए गए संदेह और (iv) अपीलकर्ता द्वारा राशि की स्वीकृति स्थापित करने में अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में असंगति के आधार पर, दोषमुक्ति का आदेश दर्ज किया है।

24. 09.12.1997 को मांग के सबूत का अभाव, पी.डब्लू. 1 द्वारा अपीलकर्ता को डीजल की खरीद के लिए राशि का भुगतान किया जाना पी.डब्लू. 2 की साक्ष्य से समर्थित है जिससे पी.डब्लू. 1 द्वारा अवैध परितोषण के रूप में भुगतान की गई राशि के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। उच्च न्यायालय ने न तो अन्य जगह उपस्थित (Plea of alibi) के बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा पर विचार किया और न ही यह माना कि विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण या विकृत था। हमारे मत में, दोषमुक्ति का आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन किसी भी कमजोरी या अवैधता या अभिव्यक्त त्रुटि से ग्रस्त नहीं है और जिन आधारों पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है, उन्हें अयुक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता, जबकि, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय के लिए न्यायोचित नहीं था और आक्षेपित निर्णय को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

25. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलकर्ता को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करने के विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर है, उसकी प्रतिभू व बंध पत्र भार से उन्मोचित माने जाते हैं।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से न्यायिक अधिकारी प्रीति मुकेश परनामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।